12.19 hrs.

RE INFORMATION GIVEN BY THE LAW MINISTER ABOUT OWNERSHIP OF UNDER-SEA LAND

श्री मधु लिमये (बांका) : आपके आदेश से मैं एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं। बहुत ही आसान और सीधा साधा मामला है। आप जो निर्णय देंगे मैं कबूल करूंगा।

मैंने बम्बई के बैंक के रिक्लेमेशन स्कीम के बारे में यहां वक्तव्य दिया था नियम 377 के तहत। उस पर कोई चार पांच सप्ताह सोचने के बाद श्री गोखले ने 2 मई को एक लिखित वक्तव्य दिया--एक्सटेम्पोर भाषण की बात मैं नहीं कर रहा हूं--लिखित वक्तवय दिया जिस में उन्होंने एक यह वाक्य कहा :

"Reference was to the scheme of reclamation formulated and pursued by the Maharashtra Government relating to the reclamation of the foreshore. In conclusion it may be stated that the reclamation of the foreshore by the Maharashtra Government under the scheme of reclamation formulated by them did not contravene Article 297 of the Constitution".

उन्होंने यह बात 2 मई को कही।

जब आपके डायरेक्शन 115 के तहत मैंने यह साबित किया कि बम्बई रिक्लेमेशन स्कीम के तहत ऐसी भी जमीनें हैं, जो टेरिटोरियल वाटर्ज में आती हैं, और श्री गोखले ने गलतबयानी की है, तो उन्होंने 8 अगस्त को अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने 2 मई को यह बात कही ही नहीं। उन्होंने 2 मई को जो कहा, वह रिकार्ड पर है और मैंने आप को इनका वाक्य उद्धृत कर बता दिया है। इस बारे में श्री गोखले को कम से कम अफसोस व्यक्त करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि 2 मई को मैंने जो वक्तव्य दिया, वह गलत था और उसके लिए मुझे अफसोस है लेकिन अगर जान-बूझ कर यह कहा जाये कि मैंने यह बात कही ही नहीं, जो कि रिकार्ड पर मौजूद है, तो फिर यह सदन कैसे चल सकता है ? आप ने भी इस के बारे में कोई आबजरवेशन नहीं किया है। आप से पहले अध्यक्ष ने इस सदन में 1966 में श्री सुब्रह्मण्यम के मामले में यह निर्णय दिया था कि अगर जान-बूझकर कोई असत्य बोले, तो यह सदन की मानहानि का सवाल बनता है। श्री गोखले ने 2 मई को कहा था कि रिक्लेमेशन की कोई भी जमीन टेरिटोरियल वाटर में नहीं हैं, लेकिन 8 अगस्त को वह कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। इस तरह यह सदन नहीं चल सकता है। इस सदन की सब प्रक्रियाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है।

मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप मंत्री महोदय पर स्ट्रिक्चर्ज पास करें। मेरी राय में तो यह प्रिविलेज का सवाल बन जाता है, क्योंकि श्री गोखले ने जान-बूझ कर असत्य बोला है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): The item No. 2 has not been disposed of. Would you put it to the House? It should have been put to vote. It is a motion.

MR. SPEAKER: I put it to the House and the House said that they accept the regrets.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I took it that it was deferred.

MR. SPEAKER: They have accepted the apology.

SHRI PILOO MODY (Godhra): I want to talk about the price of cheese in China at the moment. The matter is finished and we are on a fresh item.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): मेरे मित्र श्री मधु लिमये, ने जो मामला उठाया है, उस का सम्बन्ध तथ्यों से है। 2 मई को विधि मंत्री ने क्या कहा और 8 अगस्त को क्या कहा, यह तो रिकार्ड का विषय है। आप दोनों वक्तव्य देख सकते हैं। अगर उन्होंने जान-बूझ कर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, तो यह एक गम्भीर प्रश्न है और तब आप को यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने पर विचार करना होगा। हम पुलिस कांस्टेबल को सस्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन विधि मंत्री को सस्ता नहीं छोड़ सकते हैं।

SHRI PILOO MODY: May I make a submission on this? The other day the Minister also referred to the petition that I had filed in the High Court on this particular issue. But I am very disturbed to hear that the High Court has dismissed the petition without giving any opinions or reasons why this petition should not be heard. Therefore, I think, considering the fact that the statement was made and thereafter denied, there must be something fishy about the whole affair.

MR SPEAKER: Not at all. I can not allow any reflections to be made on the High Court.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North-East): What is your decision about Shri Madhu Limaye's matter?

MR. SPEAKER: I will look into it.

SHRI H. N. MUKERJEE No question of loookig into. We have already heard the report which has been read out from the proceedings of the House. A *prima facie* case has been made out as far as this House is concerned. Either you refer it to the Committee or decide it in the House in the Minister's presence. It will save time if it goes to the committee. But, the matter *prima facie* is very clear.

MR. SPEAKER He is referring to that I will have to ask him.

PROF. MADHU DANDAVATE: (Rajapur): It will not take even two minutes to check up the record.

SHRI H. N. MUKERJEE: It is not our fault that our time is taken by Mr. Madhu Limaye. It may be for some very good reasons. But now we are in possession of certain material with reference to our proceedings here. And I want something definite to be known here and now.. .

MR. SPEAKER: Professor, not here and now. He has given out and I will see the other statement also.

SHRI H. N. MUKERJEE: Are we to waste so much of time, no decision being taken?

MR. SPEAKER: I will have to see the other statement.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कोई जल्दबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं। आप दोनों स्टेटमेंट्स को देख लीजिये। लेकिन इस बारे में कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसे नहीं चल सकता है।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): It would help the House and the Chair also if the matter is sought to be raised under Rule 115, in the first instance so that we are able to know both sides of the case and then we can decide about the issue of privilege.

MR. SPEAKER: The Member is also given a chance, which he has exercised.

SHRI H. N. MUKERJEE: Are we to proceed in this fashion, when unnecessary waste of time is taking place, or are we to follow the usual convention that in your chamber you look into certain things, you do find time somehow or other....

MR. SPEAKER: This is what I am conveying to you. I will see the other statement also. Shri K. R. Ganesh.